राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5633/2024

निखिल पुरोहित पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार पुरोहित, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी बी-101, अपर ग्राउंड फ्लोर, नगर अपार्टमेंट, फ्रेंड्स कॉलोनी वेस्ट, नई दिल्ली, 110065। ----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव के माध्यम से, कॉलेज शिक्षा विभाग, ब्लॉक-IV, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ट, महेश नगर फाटक, बजाज नगर, जयपुर, राजस्थान, 302015।

2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, ब्लॉक-IV, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, महेश नगर फाटक, बजाज नगर, जयपुर, राजस्थान, 302015।

3. संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक), कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, ब्लॉक-IV,डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, महेश नगर फाटक, बजाज नगर, जयपुर, राजस्थान, 302015। ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री दीपक व्यास

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री मनीष पटेल, एएजी द्वारा सहायता प्रदान की गई श्री योगेश शर्मा

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश मेहता

<u>निर्णय</u>

रिपोर्ट योग्य

<u>11/07/2024</u>

1. यह मामला अधिकारियों या राज्य के अधिकारियों की विशिष्ट मानसिकता का एक गंभीर उदाहरण है, जो एक हाथ से जनता को दिए जा रहे लाभों को पेश करते हैं और दूसरे हाथ से यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी कलम चलाते हैं कि वे लाभ उन तक न पहुँचें।

2. यह न्यायालय इस मामले के चौंकाने वाले तथ्यों को देखते हुए ऐसा कहने के लिए बाध्य है, जिसमें एक प्रतिभाशाली छात्र ने नेशनल लॉ स्कूल, बैंगलोर से स्नातक - बीए एलएलबी (ऑनर्स) पूरा किया और अपनी स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज (यू.के.) चला गया और अब उसे अपनी बात साबित करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, न कि अपनी बात को सही साबित करने के लिए।

3. प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यू.के. में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बाद, याचिकाकर्ता को प्रवेश मिलना सौभाग्य की बात थी। यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि उसकी योग्यता को देखते हुए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उसकी ट्यूशन फीस माफ कर दी और तदनुसार, उसे ट्यूशन फीस नहीं बल्कि केवल अन्य खर्च वहन करने थे।

4. याचिकाकर्ता को 19.08.2021 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यू.के. से प्रवेश के लिए ऑफर लेटर मिला और वह 22.09.2021 को यू.के. चला गया, जिसके बाद 01.10.2021 को उसका कोर्स शुरू हुआ।

5. इस बीच, याचिकाकर्ता को पता चला कि राजस्थान राज्य ने राजीव गांधी शैक्षणिक उत्कृष्टता छात्रवृत्ति (जिसे आगे 'आरजीएस योजना' कहा जाएगा) नामक एक योजना शुरू की है, जिसके तहत मेधावी छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की गई है।

6. याचिकाकर्ता ने 03.11.2021 को आरजीएस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और 12,68,267/- रुपये की राशि का दावा किया।

7. याचिकाकर्ता के आवेदन पर 19.04.2022 को कार्रवाई करते हुए राज्य ने याचिकाकर्ता के खाते में 64,232/- रुपए की राशि एनईएफटी के माध्यम से वितरित की, जबकि वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था।

8. याचिकाकर्ता ने 28.06.2022 को अपना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा किया और भारत वापस आ गया तथा नई दिल्ली में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया।

9. यू.के. से लौटने के बाद याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों से संपर्क किया और उन्हें पत्र लिखकर अपने दावे की शेष राशि 12,68,267/- रुपए का भुगतान करने के लिए कहा। याचिकाकर्ता और राज्य के अधिकारियों के बीच कई पत्रों और ई-मेल का आदान-प्रदान हुआ और अंत में 27.02.2023 को संचार के माध्यम से, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा के संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि वह अपनी पारिवारिक आय के अनुसार केवल ट्यूशन फीस का हकदार था और इस प्रकार, भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता का 12,68,267/- रुपये की छात्रवृत्ति का दावा खारिज कर दिया गया।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री दीपक व्यास ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने मनमाने ढंग से कार्यवाही की है और याचिकाकर्ता के 12,68,267/- रुपये के दावे के खिलाफ, उन्होंने 64,232/- रुपये की मामूली राशि का भुगतान किया है, इस बहाने से कि वह केवल ट्यूशन फीस के लिए हकदार है और अन्य दावों के लिए नहीं।

11. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जहां तक ट्यूशन फीस का सवाल है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने खुद छात्रवृत्ति दी थी और याचिकाकर्ता ने विदेश में पढ़ाई से संबंधित अपने खर्चों की अन्य राशि प्राप्त करने के लिए योजना के तहत आवेदन किया था। उन्होंने कहा कि आरजीएस योजना के तहत आवेदन करते समय प्रतिवादियों को हर तथ्य से अवगत कराया गया था और ट्यूशन फीस की राशि का दावा भी नहीं किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता का पूरा दावा ट्यूशन फीस के अलावा अन्य राशि के लिए था, जो योजना में स्वीकार्य थी और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने योजना और रिकॉर्ड पर संबंधित दस्तावेजों के माध्यम से अदालत का रुख किया।

12. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि 05.10.2021 को अधिसूचित आरजीएस योजना के अनुसार, एक छात्र न केवल ट्यूशन फीस के लिए बल्कि अन्य राशियों जैसे वार्षिक रखरखाव भत्ता; वार्षिक आकस्मिकता और उपकरण भत्ता; वीजा शुल्क; ट्यूशन फीस; चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए भी पात्र था; हवाई यात्रा की लागत, दरों में संशोधन, आदि।

13. श्री व्यास ने प्रस्तुत किया कि उत्तर के अनुसार, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के दावे को सीमित कर दिया है या अन्य राशियों के लिए उसके दावे को खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि - अनुमेय राशि 64,232/- रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसा राज्य द्वारा दिनांक 15.06.2022 के आदेश (अंग्रेजी संस्करण, जिसका 15.07.2022 को

जारी किया गया) द्वारा योजना में लाए गए कथित संशोधन के मद्देनजर किया गया है।

14. उन्होंने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि 15.06.2022 को लागू किए गए कथित संशोधन का उपयोग याचिकाकर्ता के सही दावे को अस्वीकार करने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है और उसका हक आरजीएस योजना के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, जो उस तारीख को प्रचलित थी जब याचिकाकर्ता ने आवेदन किया था यानी 03.11.2021 को।

15. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री मनीष पटेल और उनके सहयोगी श्री योगेश शर्मा ने प्रतिपक्ष तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पास हस्तक्षेप करने लायक कोई मामला नहीं है, सबसे पहले, उन्होंने तर्क दिया कि रिट याचिका में देरी और लापरवाही है और दूसरी बात, क्योंकि याचिकाकर्ता के अधिकारों पर 30.09.2022 को मौजूद नीति के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है - जब पुष्टि पत्र जारी किया गया था, तब तक योजना में संशोधन किया जा चुका था।

16. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

17. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क है कि रिट याचिका में देरी हुई है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह अवैधता को छिपाने या इस न्यायालय का ध्यान उनकी मनमानी से हटाने के लिए किया गया है। तथ्यों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने जून, 2022 में अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की और उसका दावा 27.02.2023 को खारिज कर दिया गया। वर्तमान रिट याचिका 01.04.2024 को दायर की गई है, शायद, लगभग एक वर्ष बाद, लेकिन इसे याचिकाकर्ता के अधिकारों के लिए घातक, अत्यधिक देरी नहीं कहा जा सकता है।

18. इसके अलावा, देरी की आपत्ति उठाना राज्य के लिए उचित नहीं है, खासकर जब वह अपने घर को व्यवस्थित रखने में विफल रहा हो। यदि प्रतिवादियों ने समय पर याचिकाकर्ता के आवेदन पर कार्रवाई की होती, तो शायद याचिकाकर्ता को वह पूरी राशि मिल जाती, जो उसने अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए खर्च की थी। दुर्भाग्य से, याचिकाकर्ता को अप्रैल, 2022 के महीने में 64,232/- रुपये की मामूली राशि का भुगतान किया गया, जब वह लगभग अपना पाठ्यक्रम पूरा करने वाला था।

19. याचिकाकर्ता को शेष राशि के बारे में कुछ भी पता नहीं चला; मेल और पत्राचार का आदान-प्रदान हुआ और अंततः उसे 27.02.2023 का आदेश मिला। अंतराल अवधि (27.02.2023 से) के दौरान बीत चुके 12 महीने की समय अवधि को देरी नहीं माना जा सकता, लापरवाही तो दूर की बात है।

20. याचिकाकर्ता की पात्रता की योग्यता पर विचार करते हुए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 05.10.2021 को, राज्य सरकार ने छात्रों को उनकी पारिवारिक आय के बावजूद शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए समर्थन देने के उद्देश्य से योजना शुरू की। योजना में प्रावधान है कि कानून में मास्टर डिग्री सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक वर्ष में 200 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि लाभ 200 व्यक्तियों को दिया जाएगा, हालांकि इस शर्त के साथ कि सबसे पहले उन व्यक्तियों को लाभ दिया जाएगा जिनकी पारिवारिक आय 8,00,000/- रुपये से कम है और यदि ऐसे वर्ग के 200 व्यक्ति (जिनकी पारिवारिक आय 8,00,000/- रुपये से कम है) उपलब्ध नहीं हैं, तो छात्रवृत्ति उन छात्रों को वितरित की जाएगी, जिनकी पारिवारिक आय 8,00,000/- रुपये से अधिक है।

21. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रासंगिक बिंदु पर केवल 18 छात्र ही पात्र पाए गए और याचिकाकर्ता के मामले को आरजीएस योजना के तहत विचार के लिए लिया गया। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) ने याचिकाकर्ता को दिनांक 01.02.2022 को एक मेल भेजा था जिसमें बताया गया था कि उसे आरजीएस के तहत अनंतिम रूप से चुना गया है।

22. योजना के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक बार जब कोई उम्मीदवार योजना के लाभार्थी के रूप में चुना जाता है, तो उसकी पारिवारिक आय निरर्थक हो जाती है - पारिवारिक आय के आधार पर दी जाने वाली छात्रवृत्ति की मात्रा में कोई अंतर नहीं होता है। आरजीएस योजना के खंड 6 और खंड 8 को पुनः प्रस्तुत करना अनुचित नहीं होगा।

> "धारा 6- आय सीमा
>
> (1) अभ्यर्थी की सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय 8.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नवीनतम कर निर्धारण की एक प्रति भी आवेदन में संलग्न है।
>
> (2) यदि आय सीमा के धारा 1 के अंतर्गत दी गई अवधि के भीतर सीटें नहीं भरी जाती हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी पर भी विचार किया जाएगा, जिनकी पारिवारिक आय 8.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक है।
>
> धारा 8 - छात्रवृत्ति का मूल्य
>
> (I) वार्षिक रखरखाव भत्ता - योजना के अंतर्गत आने वाले सभी

स्तरों के पाठ्यक्रमों के लिए 10,00,000 रुपये का वार्षिक रखरखाव भत्ता।

(II) वार्षिक आकस्मिकता और उपकरण

भत्ता - पुस्तकों/आवश्यक उपकरणों/अध्ययन दौरे/टाइपिंग और थीसिस बाइंडिंग के लिए वार्षिक आकस्मिकता और उपकरण भत्ता 1,00,000 रुपये होगा।

(III) वीज़ा शुल्क - भारतीय रुपये में वास्तविक वीज़ा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

(IV) ट्यूशन फीस - वास्तविक ट्यूशन फीस ही मान्य होगी। हालांकि, यदि पुरस्कार विजेता को विश्वविद्यालय/संस्था से किसी भी रूप में कोई अन्य वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति मिलती है, तो उसे स्वीकृत राशि से काट लिया जाएगा।

(V) चिकित्सा बीमा प्रीमियम - वास्तविक रूप से लिया गया शुल्क ही मान्य होगा।

(VI) हवाई यात्रा की लागत - भारत से गंतव्य तक और वापस भारत आने के लिए सबसे छोटे मार्ग के लिए इकोनॉमी क्लास के साथ हवाई किराया मान्य होगा।

(VII) दरों में संशोधन - पहले से विदेश में अध्ययन कर रहे सभी पुरस्कार विजेता भी योजना में अनुमोदित संशोधित दरों और इसके संशोधित रूप को भविष्य में लागू करने के लिए

पात्र होंगे।

(VIII) संवितरण का तरीका - राजस्थान सरकार उपरोक्त सूचीबद्ध वित्तीय सहायता के संवितरण का तरीका तय करेगी।

23. उपर्युक्त उद्धृत खंड 8 के अवलोकन से इस बात में कोई अस्पष्टता नहीं रह जाती कि यदि कोई छात्र चयनित होता है, तो वह अपने परिवार की आय की परवाह किए बिना उपरोक्त शीर्षकों के अंतर्गत उल्लिखित सभी राशियों की छात्रवृत्ति/प्रतिपूर्ति का हकदार है।

24. इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्यूशन फीस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा ही दी गई थी और याचिकाकर्ता को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को शेष राशि का भुगतान करना था। ट्यूशन फीस के अलावा, वार्षिक रखरखाव भत्ता, वीजा शुल्क और हवाई यात्रा आदि जैसे कई शीर्षक हैं, जिन्हें राज्य को निर्धारित विश्वविद्यालयों में अधिसूचित पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को भुगतान करना था।

25. 15.06.2022 से लागू किए गए कथित संशोधन और इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय दृढ़ता से इस विचार पर है कि इसे याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। एक संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में, यह न्यायालय यह जोड़ना चाहता है कि दिशा-निर्देश जारी करने की आड़ में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय योजना में संशोधन नहीं कर सकता था; यदि योजना में संशोधन किया जाना था, तो उसे विशिष्ट आदेश द्वारा संशोधित किया जा सकता था।

26. जैसा भी हो।

27. भले ही कथित दिशा-निर्देशों को राज्य सरकार द्वारा योजना में संशोधन माना जाता है, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह 15.06.2022 को अस्तित्व में आया, जबकि याचिकाकर्ता को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से

19.08.2021 को प्रस्ताव पत्र मिला था; 03.11.2021 को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और 22.09.2021 को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करने के लिए लंदन चला गया, जो संशोधन से पहले की घटनाएँ थीं।

28. याचिकाकर्ता को 01.02.2023 को एक पत्र मिला था जिसमें बताया गया था कि उसे आरजीएस के लिए अनंतिम रूप से चुना गया है, और 19.04.2022 को उसे आंशिक भुगतान (64,232 रुपये) किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता के आवेदन पर राज्य द्वारा 19.04.2022 को कार्रवाई की गई थी, इसलिए केवल शेष राशि का भुगतान किया जाना बाकी था। यदि शेष राशि के सत्यापन और भुगतान के प्रक्रियात्मक भाग में कुछ समय लगा, जो कि राज्य के कारण था, तो वह याचिकाकर्ता के सामने यह दलील देकर दरवाजा बंद नहीं कर सकता कि अब योजना में संशोधन किया गया है।

29. रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि जब याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के साथ मामले को आगे बढ़ाया, तभी कुछ प्रश्न उठाए गए और याचिकाकर्ता से उसकी पारिवारिक आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जो कि आरजीएस योजना के नोडल अधिकारी द्वारा भेजे गए 13.07.2022 के ई-मेल से स्पष्ट है। यह स्पष्ट रूप से योजना में संशोधन की आड़ में याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने के लिए भेजा गया था।

30. याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से अपनी पारिवारिक आय प्रस्तुत की, जो प्रति वर्ष 25 लाख रुपये से अधिक थी और ऐसी पारिवारिक आय के आधार पर, प्रतिवादियों ने राज्य द्वारा दिनांक 15.06.2022 के आदेश के तहत लागू किए गए संशोधन के बहाने आरजीएस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को ठुकरा दिया।

31. दिनांक 15.06.2022 के संशोधन पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि इन संशोधनों और दिशानिर्देशों द्वारा, योजना का सार बदल दिया गया है

और पात्र राशि को पारिवारिक आय पर निर्भर कर दिया गया है, वह भी चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

32. प्रतिवादियों के अनुसार, दिनांक 15.06.2022 के संशोधन के अनुसार, 25,00,000/- रुपये से अधिक की पारिवारिक आय वाला उम्मीदवार केवल ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति का हकदार था और चूंकि याचिकाकर्ता की ट्यूशन फीस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा छूट दी गई थी या वहन की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता किसी भी अतिरिक्त राशि का हकदार नहीं है।

33. इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि प्रतिवादियों का रुख मनमाना होने के अलावा अपने आप में अस्थिर है। चूंकि याचिकाकर्ता ने 19.08.2021 को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा एलएलएम पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था और उसने 03.11.2021 को आरजीएस योजना के तहत आवेदन किया था, इसलिए उसके मामले पर उस योजना के प्रावधानों के आधार पर विचार किया जाना आवश्यक था, जो उस तारीख को प्रचलित थे, जब उसने योजना के तहत आवेदन किया था।

34. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि न केवल आवेदन करते समय बल्कि 01.02.2022 को जब याचिकाकर्ता को छात्रवृत्ति के लिए अनंतिम रूप से चुना गया था, तब भी कोई संशोधन नहीं लाया गया था। संशोधन संयोगवश याचिकाकर्ता के परिणाम (28.06.2022) की घोषणा से दस दिन पहले लाया गया था, बल्कि निश्चित रूप से उसके परीक्षा में बैठने के बाद (09.06.2022) लाया गया था।

35. यह न्यायालय बाद में पेश किए गए संशोधन के आधार पर याचिकाकर्ता के वैध दावे को दबाने या कुचलने की राज्य की कार्रवाई का समर्थन नहीं कर सकता।

36. यह ध्यान देने योग्य है कि 21.04.2022 को प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को 64,232/- रुपये की राशि वितरित की थी। पूछताछ करने पर याचिकाकर्ता को पता चला कि यह राशि वीजा शुल्क (37,122 रुपये) और दिल्ली से लंदन तक हवाई टिकट की लागत (27,110 रुपये) के लिए थी। इस प्रकार, राज्य ने न केवल याचिकाकर्ता को आरजीएस योजना के तहत अनंतिम रूप से चुना था, बल्कि इस तरह के चयन को आगे बढ़ाने के लिए भी काम किया है और दिनांक 05.10.2021 की योजना के अनुसार राशि का भुगतान किया है। इस प्रकार, राज्य का यह रुख कि याचिकाकर्ता केवल ट्यूशन फीस के लिए हकदार था, पूरी तरह से गलत साबित होता है।

37. इसके अलावा, राज्य की कार्रवाई मनमानी है और वैध अपेक्षा के सिद्धांत पर आघात करती है। 05.10.2021 को आरजीएस योजना लागू करके, राज्य ने छात्रों को एक वादा किया बल्कि एक गुलाबी तस्वीर दिखाई कि शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए विदेश जाने का उनका सपना एक वास्तविकता होगी, क्योंकि उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी, जिसमें ट्यूशन फीस और बोर्डिंग आदि के अलावा वार्षिक रखरखाव भत्ता, हवाई किराया और वीजा खर्च शामिल होंगे। याचिकाकर्ता ने इस उम्मीद में विदेश जाने का विकल्प चुना कि योजना के तहत उसके सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति राज्य द्वारा की जाएगी, राज्य ने अप्रैल, 2022 में 64,232 रुपये की राशि का भुगतान किया, लेकिन यू-टर्न ले लिया और छात्रवृत्ति से इनकार करके उसके सपनों और भविष्य की योजनाओं को चकनाचूर कर दिया। राज्य अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हट सकता जिसने पात्र छात्रों के मन में वैध विश्वास को जन्म दिया है। राज्य का ऐसा प्रतिशोधी दृष्टिकोण न केवल निंदा के योग्य है बल्कि निंदा के योग्य भी है।

38. इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता को योजना के तहत पात्र पाया गया था और दिनांक 01.02.2022 को ईमेल के माध्यम से उसे योजना के तहत उसके अनंतिम चयन के बारे में सूचित किया गया

था। इस न्यायालय के अनुसार, योजना के अंतर्गत आने वाला और पात्र पाया गया उम्मीदवार, आवेदन की तिथि (03.11.2021) को योजना के तहत उपलब्ध सभी लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

39. यह उल्लेखनीय है कि 05.10.2021 को अधिसूचित आरजीएस के खंड 8 में वित्तीय सहायता के विभिन्न शीर्ष शामिल हैं। आरजीएस के खंड 8 के उपखंड (I) और (II) में 10,00,000/- रुपये का वार्षिक रखरखाव भत्ता और 1,00,000/- रुपये का वार्षिक आकस्मिकता और उपकरण भत्ता प्रदान किया गया है। ये भत्ते वास्तविक व्यय से स्वतंत्र हैं।

40. इन भत्तों के विपरीत, अन्य शीर्ष हैं जो स्पष्ट रूप से वास्तविक शुल्क या व्यय निर्धारित करते हैं। इसलिए, जहां तक आरजीएस के खंड 8 के उपखंड (I) और (II) का संबंध है, वास्तविक व्यय का कोई सबूत आवश्यक नहीं है और केवल अन्य शीर्षों के लिए वास्तविक व्यय का सबूत आवश्यक है।

41. तथ्य यह है कि विभिन्न शीर्षों में से, प्रतिवादियों ने वीजा शुल्क (37,122 रुपये) और हवाई यात्रा (दिल्ली से लंदन) के लिए 64,232 रुपये का भुगतान किया है, जो रिकॉर्ड पर एक स्थापित तथ्य है, जिसका भुगतान वास्तविक रूप से किया जाना है। ऐसे अन्य शीर्ष हैं, जहां वास्तविक व्यय का सबूत आवश्यक है/था, जिसके बारे में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, प्रतिवादियों पर सत्यापन के बाद निश्चित रूप से ऐसी राशि का भुगतान करने का दायित्व था। याचिकाकर्ता के दावे को पूरी तरह से नकारने में प्रतिवादियों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

42. इसलिए, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

43. आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा के संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) द्वारा जारी

दिनांक 27.02.2023 को जारी किया गया विवादित संचार एतद्द्वारा निरस्त और अपास्त किया जाता है।

44. प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को देय राशि का निर्धारण आरजीएस के प्रावधानों के आधार पर करें जो आवेदन की तिथि (03.11.2021) को प्रचलित थे, जाहिर है, तथाकथित संशोधन (दिनांक 15.06.2022) के लागू होने से पहले, यहाँ की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए।

45. वर्तमान आदेश के अनुसार राशि की गणना करने के उद्देश्य से, याचिकाकर्ता आज से 10 दिनों की अवधि के भीतर वास्तविक व्यय (जहाँ भी आवश्यक हो) के साथ अपेक्षित साक्ष्य के साथ एक विवरण प्रस्तुत करेगा, साथ ही वर्तमान आदेश की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करेगा।

46. याचिकाकर्ता द्वारा 12% की दर से ब्याज दिए जाने के अनुरोध को इस उम्मीद में ठुकराया जाता है कि राज्य के अधिकारियों को सद्बुद्धि आएगी और वे सुधार योजना के घोषित उद्देश्य के अनुरूप कार्य करेंगे तथा याचिकाकर्ता को बिना किसी देरी के बकाया राशि का भुगतान करेंगे।

47. राशि का भुगतान 31.08.2024 तक किया जाए, ऐसा न करने पर, 01.09.2024 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 9% की दर से ब्याज लगेगा।

48. यद्यपि, यह एक उपयुक्त मामला है, जिसमें राज्य पर लागत लगाई जानी चाहिए, लेकिन यह न्यायालय श्री पटेल, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता के अनुरोध पर विचार करते हुए लागत लगाने से परहेज करता है।

49. स्थगन आवेदन और सभी अंतरिम आवेदन का निपटारा किया जाता है।

(दिनेश मेहता), जे.

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।